Issue of ration cards to slum Dwellers in the Country

3715. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state whether Government, are aware that weaker sections of Society, specially the slum dwellers throughout the country are facing face difficulty in getting Ration Cards and if so corrective steps taken/proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL) : Administration of Public Distribution System (PDS) including issue of ration cards is primarily the responsibility of the State Governments/U.T. Administrations. The Central Government have from time to time stressed on the need to cover the entire population specially the weaker sections of the society in all States/ Union Territories under PDS. Recently an exercise was undertaken for access of jhuggi jhonpri dwellers to PDS in the Union Territory of Delhi and over 2.17 lakh such families were issued ration cards.

कृषि भूमि का क्षेत्रफल

3716. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1989-90 के अन्त तक कृषि भूमि के क्षेत्रफल को 137.8 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो 1989-90 के अन्त तक देश में कृषि योग्य भूमि का उपयुक्त क्षेत्रफल कितना था;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नितिश कुमार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नवीनतम उपलब्ध भूमि उपयोग आंकड़ों के आधार पर देश में कुल कृष्ट क्षेत्र 155.7 मिलियन हेक्टेयर है ।

(घ) और (ङ) 1990-91 के दौरान कृषि के अन्तर्गत मृदा और जल संरक्षण के जरिए अधिक क्षेत्र को लाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. नदी घाटी परियोजना के सुवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण ।
2. बाढ़ प्रवण नदी के सुवण क्षेत्र में समोकित पनधारा प्रबन्ध ।
3. झूम खेती का नियंत्रण ।
4. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के डकैती-प्रवण क्षेत्रों में बिहड़ सुधार कार्यक्रम ।
5. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में क्षारीय मृदा का सुधार ।

1990-91 के दौरान 0.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए 94.90 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है । योजना आयोग द्वारा मृदा और जल संरक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप दिया जाना शेष है ।

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव

3717. **श्री अनन्तराय व्येशंकर दवे** :
श्री प्रभाकर राव कलवला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का विचार रखती है;